



# महाराष्ट्र शासन राजपत्र

## असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २७(२)]

मंगळवार, जुलै २१, २०१५/आषाढ ३०, शके १९३७

[पृष्ठे ६, किंमत : रुपये ४७.००

असाधारण क्रमांक ४७

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २१ जुलाई, २०१५ ई. को. पुरःस्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :-

**L. A. BILL No. XXXV OF 2015.**

**A BILL**

**FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL  
CORPORATIONS ACT.**

**विधानसभा का विधेयक क्रमांक ३५, सन् २०१५।**

**महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।**

सन १९४९ **क्योंकि** इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में अधिकतर संशोधन करना  
का ५९। इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के छियासठवे वर्ष में एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम बनाया जाता हैं :—

१. यह अधिनियम महाराष्ट्र नगर निगम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१५ कहलाए।

संक्षिप्त नाम ।

(१)

२. महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम की धारा १४९क के पश्चात् निम्न धारा निविष्ट की जायेगी सन् १९४९  
अर्थात्,— का ५९  
की धारा  
१४९ख की  
निविष्टि।

अधिसूचित  
परियोजनावाले  
शहर में स्थावर  
संपत्ति के कतिपय  
अंतरण पर  
अतिरिक्त स्टाम्प  
शुल्क।

“१४९ख (१) धारा १४९क के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय स्टाम्प शुल्क, स्थावर संपत्ति के क्रमशः विक्रय, दान और भोगधिकारी बंधक के लिखत पर एक या अधिक अत्यावश्यक नागरी परिवहन परियोजनाएँ (जिसे इसमें आगे, इस धारा में “अधिसूचित परियोजना वाले शहर” कहा गया है) और राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जाये ऐसे दिनांक पर या के पश्चात्, निष्पादित किये गये शहर में स्थित स्थावर संपत्ति के संबंधित ऐसे किसी लिखत के मामले में इस प्रकार स्थित संपत्ति के मूल्य पर विक्रय या दान के लिखत के मामले में और भोगधिकारी बंधक के लिखत के मामले में, लिखत में उपवर्णित अनुसार लिखत द्वारा प्रतिभूत रकम पर एक प्रतिशत के दर से अधिभार द्वारा बढ़ाया जायेगा और उक्त अधिनियम के अधीन तदनुसार संग्रहित की जायेगी।

(२) इस धारा के प्रयोजन के लिये, महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम की धारा २८,—

सन् १९५८  
का ६०।

(क) अधिसूचित परियोजनाओं वाले शहरों में स्थित संपत्ति ; और

(ख) अन्य किसी क्षेत्र में स्थित संपत्ति, के संबंध में अलग से उपवर्णित करने के लिये, उसमें निर्दिष्ट विवरण, विनिर्दिष्ट रूप से आवश्यक है, के रूप में पढ़ी जायेगी या प्रवर्तित होगी।

(३) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष, इस निमित्त बनाई गयी विधि द्वारा किये गये विनियोग के पश्चात्, निगम या अभिकरण, जिसने अधिसूचित परियोजना का जिम्मा लिया है, को शहर अधिसूचित परियोजनावाले में स्थित स्थावर संपत्ति के संबंध में इस धारा के अधीन उद्ग्रहीत और संग्रहित अधिभार के कारण वसूल की गई अतिरिक्त रकम के लगभग समान सहायता अनुदान का भुगतान करेगी और ऐसा सहायता अनुदान, सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रित्या में ऐसी अधिसूचित परियोजनाओं पर उपयोग में लाया जायेगा।

(४) आवश्यक धन की राशि उप-धारा (३) के अधीन, राज्य सरकार द्वारा पूर्ति करके राज्य की समेकित निधी पर प्रभारित होगी।

(५) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस धारा के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए नियम बनाएगी।

(६) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम, पूर्व प्रकाशित शर्त के अध्वधीन होंगे।

(७) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, उसके बनाए जाने के बाद, यथा संभव शीघ्र राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिनों की अवधि के लिए चाहे एक सत्र या बाद के दो या अधिक सत्रों को मिलाकर रखा जायेगा और यदि उस सत्र के, जिसमें उसे इस प्रकार रखा गया है या सद्य अनुवर्ती सत्र या सत्रों के अवसान से पूर्व दोनों सदन नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए राजी होते हैं, या दोनों सदन इस बात के लिए सहमत होते हैं, कि नियम नहीं बनाया जाए और ऐसे विनिश्चय को राजपत्र में अधिसूचित करते हैं, तो नियम, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति निष्प्रभावी हो जायेगा ; तथापि, ऐसा कोई उपांतरण या बातिलीकरण, उस नियम के अधीन पहले की गई या किए जाने से छोड़ी गई किसी बात की विधिमन्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।”

**स्पष्टीकरण.**—“इस धारा के प्रयोजनों के लिए”; “अधिसूचित परियोजना” पद का तात्पर्य, बड़ी मात्रा में द्रुतगति परिवहन प्रणाली जैसे कि मेट्रो रेल, मोनो रेल, बस द्रुतगति परिवहन प्रणाली से संबंधित अत्यावश्यक महत्वपूर्ण नागरी परिवहन परियोजना से है और उसके अंतर्गत पथकर मुक्त मार्ग, सी-लिंक आदि से संबंधित जो राज्य सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो स्वयंद्वारा या योजना प्राधिकरण, नए शहर विकास प्राधिकरण और अन्य कानूनी प्राधिकरण के जरिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या कंपनी अधिनियम, २०१३ के उपबंधों २०१३ का १८ के अधीन निगमित सरकारी कंपनी या तत्समय प्रवृत्त अधीन कंपनियों से संबंधित किसी अन्य विधि द्वारा नियंत्रित ऐसी परियोजना हाथ में लेने का उसका आशय घोषित करते हैं।

**उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।**

पथकर मुक्त राजमार्ग, जिसमें सी-लैंक आदि समेत मेट्रो रेल, मोनो रेल, तेज बस परिवहन प्रणाली जैसी व्यापक तेज परिवहन प्रणाली से संबंधित अत्यावश्यक महत्वपूर्ण नगरीय परिवहन परियोजना को कार्यान्वित करने की जरूरत को राज्य सरकार ने मान्यता दी है। निगम या अभिकरण जिसने अधिसूचित अत्यावश्यक महत्वपूर्ण नगरीय परिवहन परियोजना हाथ में ली है इस प्रयोजन के लिए उसकी व्यवस्था पर पर्याप्त निधि है उसे सुनिश्चित करने की दृष्टि से, उन शहरों में जहाँ ऐसी अत्यावश्यक महत्वपूर्ण नगरीय परिवहन परियोजना हाथ में ली है वहाँ क्रमशः स्थावर संपत्ति के उद्ग्रहणिय स्टाम्प शुल्क पर क्रय, उपहार तथा उपभोक्ता बंधक के लिखत पर अधिशुल्क का उद्ग्रहण करना इष्टकर समझा गया है।

२. इसलिए, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम (सन् १९४९ का ५९) में यथोचित संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

३. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,

दिनांकित १४ जुलाई २०१५ ।

**देवेंद्र फडणवीस,**

मुख्यमंत्री।

**प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।**

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजनार्थ, निम्नलिखित प्रस्ताव अंतर्गस्त हैं, अर्थात् :—

**खंड २.**—इस खंड का आशय, महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में (सन् १९४९ का ५९) एक नई धारा १४९ख को निविष्ट करना है। प्रस्तावित नई धारा १४९ख के अधीन, राज्य सरकार को,—

(एक) उप-धारा (१) में महाराष्ट्र स्टाम्प अधिनियम (सन् १९५८ का ६०) के अधीन एक या अधिक अत्यावश्यक महत्वपूर्ण नगरीय परिवहन परियोजनाएँ जिस शहर में स्थित हैं, उद्ग्रहणीय स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के साथ प्रभारित स्थावर संपत्ति के विक्रय, उपहार या उपभोक्ता बंधक के लिखत निष्पादित किए जाने वाले दिनांक को या के पश्चात्, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, विहित करने ;

(दो) उप-धारा (५) में, उक्त धारा १४९ख के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियम बनाने की, शक्ति राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिए, उपरोल्लिखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप के हैं।

### वित्तीय ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक का खंड २ महाराष्ट्र नगर निगम अधिनियम में एक नई धारा १४९ख को निविष्ट करने का आशय रखता है। प्रस्तुत विधेयक यह उपबंध करता है कि, जिस शहर में एक या अधिक अत्यावश्यक महत्त्वपूर्ण नगरीय परिवहन परियोजनाएँ हाथ में ली गई हैं उस शहर के निगम को प्रत्येक वर्ष सम्यक् विनियोग अदा करने के पश्चात्, राज्य सरकार स्थावर संपत्ति के क्रय, उपहार तथा उपभोक्ता बंधक के लिए लिखत के निष्पादन के संबंध में लगभग उद्ग्रहित और संग्रहित अधिशुल्क की राशि के समान सहायक अनुदान देगी। प्रस्तुत विधेयक आगे यह उपबंध करता है कि, इस प्रयोजन के लिए आवश्यक राशि राज्य की संचित निधि पर प्रभारित की जाएगी।

सहायक अनुदान के रूप में अदा की जानेवाली राशि संग्रहित अधिशुल्क के उद्ग्रहण पर निर्भर होगी। ऐसी राशि जो सहायक अनुदान के रूप में है वह इस स्तर पर निर्धारित नहीं की जा सकेगी।

(यथार्थ अनुवाद),

**श्रीमती मंजूषा कुलकर्णी,**

भाषा संचालक,

महाराष्ट्र राज्य।

**भारतीय संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल की अनुशंसा**

(महाराष्ट्र शासन, विधि व न्याय विभाग, आदेश की प्रत)

भारत संविधान के अनुच्छेद २०७ के खंड (१) और (३) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र नगर निगम (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१५ ई. पर विचार करने की अनुशंसा करते हैं ।

**विधान भवन :**

मुंबई,

दिनांकित २१ जुलाई २०१५ ।

**डॉ. अनंत कळसे,**

प्रधान सचिव

महाराष्ट्र विधानसभा ।